जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

कोटा

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 51 संख्याः 79 प्रभात कोटा, गुरूवार 1 जनवरी, 2026 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ममता बजर्नी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं

उनका मुस्लिम वोट बैंक बिखरने सा लग रहा है, अतः हिंदू मतदाता को लुभाने की पूरी कोशिश में हैं, पर, क्या वे चार महीने में इस लक्ष्य तक पहुँच पाएंगी, जबकि, प्रतिस्पर्धा हिंदुवादी भाजपा से है

- ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की शुरुआत, कांग्रेस छोड़कर की थी तथा उस समय उनकी रणनीति थी, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कांग्रेस छुड़वाकर अपनी पार्टी में शामिल करें।
- उनका दूसरा कदम था, कांग्रेस-वामपंथी पार्टियों के मुस्लिम समर्थकों को उनकी मूल पार्टी से अलग कर अपना मुस्लिम वोट बैंक तैयार करना। वे इस रणनीति को भी बखूबी पूरा कर ले गईं।
- पर, उनका मुस्लिम वोट बैंक बिखर रहा है, क्योंकि, मुस्लिम नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब जागृत हो गई है और वो लोग अपनी-अपनी पार्टी बनाने की कोशिश में हैं। उदाहरण के लिए, मुर्शिदाबाद के मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर। इन मुस्लिम नेताओं की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की क्षमता नहीं है, ममता जी में।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अभी कम से कम छह महीने दूर हों, लेकिन यहां बड़े राजनीतिक नेताओं की गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और हर ओर राजनीतिक जोड़-तोड़ दिखाई दे रहा है।

इन्हीं नेताओं में से एक हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कभी न सिर्फ राज्य, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे, और अब वे अपने गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में अपना खोया हुआ प्रभुत्व वापस पाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बाद में लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता भी रहे हैं।

ममता बनर्जी ने अधीर चौधरी को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में हराने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था और इसके लिए उन्होंने विरोधी दलों के साथ कई गठबंधन किए। नतीजतन अधीर चौधरी अपनी सीट हार गए और उसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं का विश्वास भी खो दिया।

इसके बाद अधीर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन उनकी जगह लेने वाला व्यक्ति इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह अयोग्य साबित हुआ और बंगाल में कांग्रेस लगभग खत्म ही हो गई। ममता के सत्ता में आने के बाद हुए ध्रुवीकरण के चलते कांग्रेस की सारी प्रासंगिकता खत्म हो गई और उसका वोट बैंक भी बिखर गया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति से करें'

जयपुर, 31 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दौसा जिले के महुआ ब्लॉक में साल 1997 में तैनात महिला शिक्षक के सेवाकाल की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए उसे समस्त सेवा परिलाभ अदा करे। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सरूपी बाई मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति साल 1997 में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर हुई थी।

- हाई कोर्ट ने महिला शिक्षक की याचिका पर प्रथम नियुक्ति से सेवा परिलाभ देने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता ने 4 मार्च, 1997 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। बाद में राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं देने का निर्णय लिया और इस अवधि में उसकी सेवा ब्रेक मानी गई। इसके साथ ही उसे एक जुलाई से सेवा में नियमित मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान और वरिष्ठता आदि का लाभ दिया। याचिका में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति मार्च माह में ही हो गई थी। ऐसे में उसकी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सरकार ने वोडाफोन को नए साल जबरदस्त तोहफा दिया

वोडाफोन की देनदारी, जो लगभग 87,695 करोड़ रुपये है, उसे सरकार ने ''फ्रीज़'' किया तथा पाँच साल बाद भुगतान आरंभ होगा और इस तरह वित्तीय वर्ष 2031-32 से कंपनी भुगतान की अदायगी शुरु करेगी

- यह माना जा रहा है कि सरकार ने यह रिलीफ पैकेज इसलिए दिया है, क्योंकि इससे ही सरकार अपने ''इन्वेस्टमैंट'' को सुरक्षित कर सकती है। जैसा कि विदित ही है सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी वोडाफोन में है।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। एक और बड़े व्यवसाय की मदद करने के लिए, मोदी सरकार ने वोडाफोन आइडिया को नए साल का तोहफा दिया तथा महत्वपूर्ण राहत पैकेज मंजूर किया है, जिसके तहत कंपनी के लंबित कर्ज का एक बड़ा हिस्सा स्थगित कर दिया गया और भुगतान पर पांच साल का मोरेटोरियम दिया गया है अर्थात 5 साल तक उन्हें भुगतान नहीं करना होगा। यह कदम कर्ज में डूबी इस दूरसंचार कंपनी के लिए एक जीवन रेखा माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के बकाया एडजस्टेड ग्रोस रैवुन्यु (एजीआर) को फ्रीज करने की मंजूरी दी तक जो कि 87,695 करोड़ रुपये तक है। इसमें सबसे उदार और अनुकूल शर्तें दी गई हैं।

इस फैसले के जानकार सूत्रों के अनुसार, कंपनी 2031-32 वित्तीय वर्ष से इन कर्जों का भुगतान शुरू करेगी और पूरे कर्ज को 2040-41 तक निपटा दिया जाएगा।

एजीआर कर्ज वह राशि है, जो दूरसंचार कंपनियां सरकार को समायोजित सकल राजस्व के आधार पर भुगतान करती हैं, जो लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना का आधार होती है। एजीआर की परिभाषा में ऑपरेटरों द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल हैं, जिनमें गैर-दूरसंचार आय, जैसे ब्याज, किराया और संपत्ति बिक्री भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया, इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के एजीआर कर्ज, जो सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अंतिम रूप से तय किए गए थे, 2025-26 से 2030-31 के बीच बिना किसी संशोधन के चुका दिये जायेंगे।

वोडाफोन आइडिया लंबे समय से एक वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसका कारण तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा, भारी कर्ज का बोझ और राजस्व परिभाषा में बदलाव के कारण बढ़े हुये एजीआर कर्ज हैं।

कंपनी लगातार घाटे का सामना कर रही है, इसके ग्राहक आधार में गिरावट आई है और नेटवर्क विस्तार में निवेश करने की क्षमता सीमित हो गई है, जबकि प्रतिस्पर्धी कंपनियां 4 और 5 रोलआउट में आगे बढ़ रही हैं

हालांकि सरकार की कई राहत योजनाओं और कर्ज को इक्विटी में बदलने से ऑपरेटर को बनाए रखने में मदद मिली है, लेकिन इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण अब भी नीति

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अजित पवार ने की भाजपा की खुली अवहेलना

भाजपा की आपत्ति के बावजूद नवाब मलिक के तीन रिश्तेदारों को बीएमसी चुनाव में टिकट दिया

- अजित पवार ने नवाब मलिक को मुम्बई में एनसीपी की चुनाव प्रबंध समिति का चेयरमैन नियुक्त किया था, जिस पर भाजपा ने आपत्ति जताई, क्योंकि मलिक पर आरोप है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के परिजनों व रिश्तेदारों से जमीन के सौदे किए हैं। इस संबंध में मलिक को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था।
- लेकिन अजित पवार ने भाजपा की नाखुशी की लेश मात्र भी परवाह नहीं की, उल्टे नवाब मलिक के भाई, बहिन और भतीजी को बीएमसी चुनावों में टिकट दे दिया।
- ज्ञातव्य है कि बीमएसी चुनावों में भाजपा एकनाथ शिंदे और अठावले की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अजित पवार को साथ नहीं लिया गया है।

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 31 दिसम्बर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के परिवार के तीन सदस्यों को मुंबई नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया है।

पवार ने मलिक को मुंबई के लिए एनसीपी की चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। भाजपा ने मलिक के नाम पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उनके खिलाफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ संपत्ति सौदों में लिप्त होने के आरोप हैं।

प्रसंगवश बता दें कि मलिक की बेटी सना मलिक मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी की विधायक हैं।

बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी), जिसमें 227 निर्वाचन क्षेत्र हैं, में भाजपा, जो महा युति-एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना और अन्य पार्टियों, जैसे रामदास अठावले के नेतृत्व वाली आरपीआई (अठावले) के साथ गठबंधन कर रही है, जबकि एनसीपी को छोड़ दिया गया है।

एनसीपी के मुंबई में 100 से

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली ने सबसे ठंडे दिसंबर का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोडा

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर। नये साल से ठीक पहले राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गयी और बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान गिरकर 14.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह बीते 11 वर्षों में दिसंबर

- साल के आखिरी दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सैंटिग्रेड दर्ज किया। दिल्ली में सन् 2014 में दिसंबर में इतना कम तापमान दर्ज किया गया था।

महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक, इससे पहले दिसंबर 2014 में 14.0 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। पिछले 24 घंटों में तापमान में सात

(शेष पृष्ठ 5 पर)

संघ की मदद से मोदी की जगह प्र.मंत्री बनने का ख्वाब संजोए हैं चंद्रबाबू

भागवत की हालिया तिरुपति यात्रा में भागवत व चंद्रबाबू के बीच जो निकटता दिखी, उससे अटकलों का बाज़ार गर्म है

- नायडू की सोच है कि मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं, इसलिए भागवत उन्हें पद छोड़ने को कह सकते हैं, उसके बाद भागवत नायडू का नाम आगे बढ़ा सकते हैं।
- मजे की बात है कि नायडू, जो मोदी से 5 माह बड़े हैं, पहले ही 75 के हो चुके हैं, पर, चंद्रबाबू व उनके समर्थकों का कहना है कि 75 साल का नियम भाजपा पर लागू होता है उन पर नहीं।
- अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि संघ नेतृत्व भाजपा में हालिया हुए फेरबदल से खुश नहीं है, खासकर बिहार के एक विधायक नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से। संघ को भी इस फैसले की सूचना अंतिम क्षणों में दी गई थी।
- नायडू के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनकी भाजपा-आरएसएस के इकोसिस्टम पर पैनी नज़र है और अगर उन्हें मौका मिला तो वे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने से हिचकेंगे नहीं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्र बाबू नायडू नरेन्द्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे मोदी को 75 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास लेने का आदेश दे सकते हैं, जो उम्र सीमा उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के लिए तय की थी।

इस प्रकार, नायडू और भागवत के बीच की नज़दीकी को एक संभावित महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। तिरुपति में भागवत से हाल की हुई उनकी मीटिंग और फिर अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन ने आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की तीव्र अटकलों को जन्म दिया है।

नायडू, मोदी से पांच महीने बड़े हैं, और वे अप्रैल में 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, जबकि मोदी ने यह उम्र सितंबर में हासिल की। लेकिन टीडीपी के नेताओं का कहना है कि 75 वर्ष की आयु सीमा केवल भाजपा नेताओं पर लागू है, न कि नायडू पर। ज्ञातव्य है कि भागवत भी मोदी से छह दिन बड़े हैं, क्योंकि वे 11 सितंबर 1950 को जन्मे थे।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नायडू की गतिविधियों को विचार-विमर्श के बाद के सावधानीपूर्ण संकेत माना जा सकता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की अपील की है, जिसके कारण एक बहस भी शुरु हो गई है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भारत ने निमेसुलाइड दवा पर बैन लगाया

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सोमवार को ऐसी सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें निमेसुलाइड की

- यह दवा बुखार तथा दर्द में दी जाती है पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसके साइडइफैक्ट्स को देखते हुए इस पर रोक लगाने का सुझाव दिया था, जिस पर भारत सरकार ने अमल किया है।

मात्रा 100 मिलीग्राम से अधिक है।

मंत्रालय ने एक वर्ष पहले ही मवेशियों के लिए भी इसे प्रतिबंधित कर दिया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'यूक्रेन, रूस का लक्ष्य नहीं, बल्कि चिंगारी है, बड़े विस्फोट का रास्ता प्रशस्त करने के लिए'

यूक्रेन के इंटैलिजैंस चीफ, ले.जनरल कायरीलो बुडानोव ने चेतावनी दी कि राष्ट्रपति पुतिन बड़े और व्यापक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पूरा यूरोप ही नहीं, बल्कि सभी नाटो देश, रूस से सीधे टक्कर में आ जाएंगे

- ले.जनरल बुडानोव के अनुसार, पहले रूस ने इस सामरिक युद्ध के लिए 2030 का समय मुकर्रर किया था, अब इस डैडलाइन का पुनर्निर्धारण किया गया और यह विस्फोट 2027 में करना तय किया गया है।
- ले.जनरल बुडानोव के अनुसार, मॉस्को की इस महत्वाकांक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार है, यह मानना कि वह एक साम्राज्य है और साम्राज्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपना प्रभाव व राज्य का विस्तार करते रहना जरूरी है।

- सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। कूटनीति ठप हो गई है और यूक्रेन युद्ध का समाधान दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा, इसी बीच कीव से एक डरावनी चेतावनी आई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध भले ही एक छोटे युद्ध का प्रारंभ हो, पर एक बड़े और कहीं अधिक खतरनाक वैश्विक टकराव की ओर बढ़ सकता है।

यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कायरिलो बुडानोव ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीन पुतिन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है और नाटो को रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव में घसीट सकता है। यह वास्तविक संभावना पैदा कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध इस दशक के भीतर या शायद इससे भी जल्द छिड़ सकता है।

बुडानोव के अनुसार, रूस की युद्ध योजनाएँ यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं। उनका दावा है कि मॉस्को, नाटो-समर्थित देशों को निशाना बनाकर यूरोप में संघर्ष को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य शक्ति के माध्यम से महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को नया आकार देना है। खुफिया मूल्यांकन का सबसे डरावना पहलू यह है कि रूस 2027 तक नाटो और यूरोपीय संघ के तीन सदस्य देशों- एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कब्जे में लेने की योजना बना रहा है।

बुडानोव ने कहा कि रूस की योजना 2030 तक इस कार्यवाही के लिए तैयार होने की थी, लेकिन अब क्रेमलिन ने अपनी योजनाओं को तेज़ कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी, ''समय सीमा में संशोधन किया गया है।'' ''रूस ने अब 2027 तक युद्ध के लिए तैयार होने का लक्ष्य तय किया है।''

कथित युद्ध योजनाओं के तहत, तीन बाल्टिक राज्य पूरी तरह से कब्जे में ले लिए जाएंगे। पोलैंड, इस बीच, अलग तरह से देखा जा रहा है, इसे वह क्षेत्र माना जाता है, जिस पर कब्जा किया जाए, बल्कि इसे सैन्य हमलों का लक्ष्य माना जाता है, जो नाटो संचालन को समर्थन देने की उसकी क्षमता को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बुडानोव ने जोर देकर कहा कि पोलैंड पर तत्काल कोई रूसी आक्रमण का संकेत नहीं हैं, लेकिन यह मॉस्को के निशाने पर है।

नाटो सदस्य पर कोई भी हमला कहीं अधिक गंभीर परिणामों का कारण बनेगा, इसका प्रभाव पूर्वी यूरोप के पार तक होगा। इस तरह के हमले से नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 को लागू किया जाएगा, जो एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमले के रूप में मानता है और इसके साथ ही सभी सहयोगी देशों को बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब होगा, रूस और नाटो गठबंधन के बीच सीधा सैन्य टकराव, एक पूर्ण-स्तरीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जाता है।

बुडानोव ने मॉस्को की महत्वाकांक्षाओं को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। माना जाता है कि ''एक साम्राज्य का अस्तित्व रहे, इसके लिए हमेशा विस्तार करना होता है, प्रभाव

(शेष पृष्ठ 5 पर)

इंदौर में दूषित जल से अब तक 12 मौत

इंदौर, 31 दिसंबर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीले पानी से हुई मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को पांच माह के अव्यान साहू की मौत हो गई। इसके अलावा, एक बुर्जुग की मौत भी हुई है। बुधवार को भी नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक

- इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। हाई कोर्ट ने प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

1100 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। भागीरथपुरा में बुधवार को कुछ अन्य मौतें भी हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मौत की वजह डायरिया नहीं मान रहा है। अब तक जहरीले पानी से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के चार नए मामले बुधवार को सामने आए है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)